

01. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया आम बजट। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए अंठावन दशमलव नौ हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की।
02. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा— इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है।
03. करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपये की गयी।
04. और, सर्वोच्च न्यायालय ने नीट—यूजी दो हजार चौबीस की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इन्कार किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष दो हजार चौबीस—पच्चीस का केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की गयी है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के अन्तर्गत आर्थिक प्रावधान किये गये हैं।

—बाईट—

प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार सम्बद्ध प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। इस पर बत्तीस हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। बजट में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किये जाने की घोषणा की गयी है।

बजट में किसान, महिला, युवा, उद्यमी समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आम बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख छियासठ हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गयी है। सरकार, जनजातीय समुदायों की सामाजिक—आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का

आवंटन किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

---

केन्द्रीय बजट में करदाताओं को भी विशेष राहत देने की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने का ऐलान किया है। श्रीमती सीतारमन में आयकर अधिनियम उन्नीस सौ इकसठ की व्यापक समीक्षा करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपये कर दी है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को पन्द्रह हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये करने का प्रावधान किया गया है। नई कर व्यवस्था में टेक्स स्लैब को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी, सात से दस लाख रुपये की आय पर दस फीसदी और दस से बारह लाख रुपये तक की आय पर पन्द्रह फीसदी का कर लगेगा।

---

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विभिन्न उत्पादों के कस्टम ड्यूटी में कमी की है, जिससे सोना-चांदी, मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोलर पैनल, चमड़े के सामान, एक्स-रे मशीन, मछलियों का दाना समेत कई उत्पाद सस्ते होंगे। कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा लिये जाने से ये दवाएं काफी सस्ती हो जायेंगी। वहीं, प्लास्टिक उत्पाद और टेलीकॉम से जुड़े सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गयी है। इससे इन उत्पादों की कीमत में वृद्धि होगी।

---

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 से समाज के हर वर्ग को मदद मिलेगी और उनका सशक्तिकरण होगा। उन्होंने जोर दिया कि इस बजट से गांव, कमजोर वर्ग और किसान समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से युवाओं को अवसर मिलेंगे।

---बाईट---

---

वित्त मंत्री ने आम बजट में बिहार के चहुमुखी विकास के लिए अंठावन दशमलव नौ हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। एक रिपोर्ट-

—बाईट—

बजट में राज्य में सड़क संरचना के विकास पर छब्बीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पटना- पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोध गया, वैशाली तथा दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने का कार्य किया जायेगा। इसके साथ ही इक्कीस हजार करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर के पीरपैती में विद्युत परियोजना लगायी जायेगी। बजट में काशी की तर्ज पर बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर का विकास, राजगीर में सप्तऋषि योजना और नालंदा में पर्यटन के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किये गये हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि बिहार को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए नेपाल के साथ मिलकर कार्ययोजना बनायी जायेगी। बजट में कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनिकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए ग्यारह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अमृतसर, कोलकाता, औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान किये जाने की भी घोषणा की गयी है। समाचार कक्ष से कल्पना झा।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट में बिहार की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज समेत विभिन्न बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है, इससे राज्य की प्रगति का नया मार्ग खुलेगा।

—बाईट—

वित्त मंत्री की घोषणाओं का राज्य के सियासी, सामाजिक और औद्योगिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बजट का स्वागत करते हुये कहा कि इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी।

—बाईट—

जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट में बिहार को दी गयी वित्तीय सहायता अभूतपूर्व है।

—बाईट—

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित पैकेज का स्वागत करते हुये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है।

—बाईट—

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को संतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।

---बाईट---

वहीं, विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजन बताया है। राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार बड़े जोर-शोर से बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हो जाना चाहिए।

---बाईट---

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी दो हजार चौबीस की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

और अब अंत में मुख्य समाचार, एक बार फिर....

01. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया आम बजट। बिहार के चहुमुखी विकास के लिए अंठावन दशमलव नौ हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा की।
02. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा— इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है।
03. करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रुपये की गयी।
04. और, सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी दो हजार चौबीस की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इन्कार किया।

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।